जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:230 दिनांक:31-07-2024 बुधवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में मंगलवार तड़के कई जगहों पर भारी बारिश के बाद हुईं भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है जबकि 98 से अधिक लोग लापता हैं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया गया 48.21 लाख करोड़ का बजट मंगलवार को लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले बजट 2024 (ॅलू 2024) पर करीब 27 घंटे से अधिक चर्चा हुई। इसमें 125 सदस्यों ने भाग लिया

वायनाड में लैंडस्लाइड- 119 की मौत, 400 लापता...4 घंटे में 3 भूस्खलन, 4 गांव बहे,

वायनाड/नई दिल्ली/भोपाल(ईएमएस)। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में घर, पुल, सडक़ें और गाडियां भी बह गईं। अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। 116 अस्पताल में हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एयरफोर्स के 2 हेलिकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। इधर, केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। केरल में हादसे के बाद मप्र सरकार की भी चिंता बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि मप्र में कई पुल और बांध आज इस स्थिति में हैं कि वे कभी भी दरक सकते हैं। उम्रदराज हो चुके पुलों से आज भी हजारों वाहन रोज निकल रहे हैं।

मप्र में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कुल 80 ब्रिजों को मरम्मत की जरूरत है। हादसों की आशंका के मद्देनजर अब इन्हें तत्काल सुधार की श्रेणी में रखा गया है। पीडब्ल्यूडी ने ब्रिज के संबंध में प्रदेश स्तरीय रिपोर्ट सरकार को भेजी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें 65 पुल ऐसे हैं जो 68 साल पुराने हैं। इसका निर्माण साल 1956 से 1961 के बीच किया गया था। बीते विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को भेजी गई पीडब्ल्यूडी के ब्रिज जोन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में खस्ताहाल ब्रिजों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जबलपुर, इंदौर और उज्जैन संभाग में ब्रिजों की स्थिति खराब है। वर्ष 2021, अक्टूबर में ग्वालियर और चंबल संभाग में बाढ़ के दौरान सात पुल टूट गए थे।

आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली (ईएमएस)। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है। एक ज्ञापन में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के अ?धिका?रियों ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य भारी बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में वहां रहने वाले लाखों लोग अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आयकर रिटर्न फाइल करने की आ?खिरी तारीख को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। हालांकि आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सैलरीड पर्सन को एंप्लॉयर के जरिये पहले ही टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ मिल गया होगा। इससे उनके फॉर्म-16 में सभी डिडक्शन की जानकारी होगी। वह वहां से अपने डिडक्शन को चेक कर सकते हैं।

हमलावर योगी......एंटी रोमियो स्क्वाड गठन पर सपा रोई, प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले हमने शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड इसका उदाहरण है। मुझे दुख होता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ तब सबसे पहले इसका विरोध सपाईयों ने किया था। ये बोलने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराधों के मामलों में सीधे और किसी और तौर पर सपा के लोग ही जुड़े हैं। महिला सुरक्षा के लिए ये समाजवादी खुद ही एक गंभीर खतरा हैं। हमारी सरकार प्रदेश में हर बेटी को और हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सुरक्षा से संबंधित प्रश्न का जवाब देकर सीएम योगी ने कहा कि महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे दो प्रकार के होते हैं। एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर। दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। 2016 की तुलना में सभी तरह के मामलों में कमी दिखाई दी है। 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटनाओं में 2023-24 के बीच में लगभग 17.5 प्रतिशत की कमी आई है। 2016 की तुलना में 2023-24 में बलात्कार की घटनाओं में 25.30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान 24 हजार 402 प्रकरणों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 2017-24 के बीच पॉक्सो एक्ट में 9875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है।

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में इस दिशा में कई अन्य प्रयास भी हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज को लेकर भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, उस हमारी सरकार ने 2018 में ही सक्रिय कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के अंदर प्रॉपर मॉनीटरिंग की गई है, जिसका परिणाम है कि पेंडेंसी रेट में तेजी से कमी दर्ज की गई है। पेंडेंसी रेट में उत्तर प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि इन मामलों के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ई प्रॉसीक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। इस दौरान लगभग 98 प्रतिशत से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक महिला थाना स्थापित करने के साथ ही एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में 1585 थानों में अलग से एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है।

सीएम योगी ने बताया कि 2020 से हमारी सरकार ने मिशन शक्ति के अभियान को बढ़ाया है। इसके तहत पिछले 7 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। जहां 2017 के पहले तक कुल 10 हजार महिला कार्मिकों की भर्ती हुई थी, जबकि 2017 से 2022-23 के बीच 20 हजार से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में सफलता प्राप्त हुई है। यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी महिला पुलिस कार्मिकों की भर्तियां हुई थीं, उससे दोगुनी भर्ती महज 5 वर्षों में हमारी सरकार ने की है।

पेपर लीक की तरह रेल हादसों पर रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार : अखिलेश

नई दिल्ली,(ईएमएस)। झारखंड में हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के 18 कोच पटरी से उतर गए। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार पेपर लीक की तरह ही रेल हादसों पर रिकॉर्ड बनाना चाहती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया सरकार ने और अब रेल हादसे....सरकार सिर्फ बड़े दावा करती है। लोगों की जान जा रही है। ऐसे हादसे भविष्य में न हों सरकार कुछ करे। वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस हादसे को लेकर कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए ।

बजट में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है, उसे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ - निर्मला सीतारमन

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है, उसे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सीतारमन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के समय में सभी वित्तीय वर्ष में पेश किए गए बजट की बातों से विपक्ष पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा, 2004-05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं था। 2009-10 के बजट में यूपी और बिहार को छोड़कर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया। 2010-11 के बजट में 19 राज्यों का जिक्र नहीं था। 2014-15 में 10 राज्यों का जिक्र नहीं था। आप बताइए जिन राज्यों का बजट में नाम नहीं था, क्या उन्हें पैसे नहीं दिए गए?

वित्त मंत्री ने कहा, मैं उस समय यूपीए सरकार का हिस्सा रहे सदस्यों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या सरकार की तरफ से पैसा केवल 17 राज्यों को गया? क्या बाकी राज्यों को उन्होंने पैसा रोक दिया था? सीतारमन ने एक बार फिर से दोहराया, बजट में किसी राज्य का नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है, उसे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है।

पेरिस ओलंपिक : मनु ने सरबजोत के साथ 10 मीटर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास

एक ही ओलंपिक में पहली बार किसी भारतीय ने जीते दो पदक

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। मनु का ये दूसरा पदक है, इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ ही मनु ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली खिलाड़ी बन गयी हैं जिसने एक ही ओलंपिक में दो पदक जीते हैं।

मनु और सरबजोत ने 10 मीटर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में दक्षिण कोरिया की ली वोन्हो और ओह ये जिन को 16-10 से हराया। गौरतलब है कि मनु से पहले ओलंपिक इतिहास में केवल दो भारतीय खिलाड़ी ही ऐसे हुए हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीते हैं। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार ने साल 2008 और 2012 में कुश्ती में पदक जीते थे। इसी तरह बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने साल 2016 और 2020 में पदक जीते थे।

मनु और सरबजोत को मिश्रित टीम इवेंट में पहले शॉट्स में हार मिली थी पर इसके बाद लगातार तीन शॉट्स में जीत हासिल करते हुए इस जोड़ी ने 6-2 की बढ़त हासिल कर ली। लगातार चौथे शॉट्स में जीत हासिल करते हुए भारत ने 8-2 की बढ़त बना ली।

वहीं कोरिया ने 5 शॉट के बाद टाइम आउट लिया था और वापसी करते ही भारत के खिलाफ 2 अंक हासिल किया। भारत के पास अब 8-4 की बढ़त हो गयी। आठवें शॉट में मनु विफल रही और पहली बार 10 से कम स्कोर किया। कोरियाई जोड़ी ने इस सीरीज को जीता पर भारतीय जोड़ी इसके बाद भी 10-6 से आगे रही। 10वीं सीरीज में जीत हासिल करने के साथ ही भारत ने बढ़त को 14-6 कर लिया।

भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली

2025 में होगा यह मेंस क्रिकेट इवेंट; 2027 में बांग्लादेश में खेला जाएगा

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत 2025 में टी-20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह 2026 में देश में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। भारत को मेंस एशिया कप के इतिहास में दूसरी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले, 1990 में मिली थी। इसके बाद एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसी साल (2027 में) साउथ अफ्रीकी सरजमीं पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है।

एशिया क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी किए गए इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, भारत 2025 में मेंस एशिया कप की मेजबानी करेगा, जो टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। वहीं, 2027 का एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। 2027 का एशिया कप वनडे फॉर्मेट में ही होगा।

भारत सबसे सफल टीम

एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप अपने नाम किया है। इनमें 7 बार यह वनडे फॉर्मेट में और 1 बार टी-20 फॉर्मेट में हुआ। भारत के बाद श्रीलंका सबसे कामयाब टीम है। वह 6 बार यह ट्रॉफी जीती है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। वह 2 बार यह टाइटल जीता है।

वन रैंक वन पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार पर 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेना में रिटायर्ड स्थायी कैप्टन को पेंशन के भुगतान से संबंधित वन रैंक वन पेंशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा तीन महीने में फैसला लेने की मांग वाली दलील ठुकरा दी है और केन्द्र सरकार पर 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते मे जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर तक इस मसले पर केन्द्र सरकार को फैसला लेने का आदेश दिया। इस मामले पर केन्द्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिए जाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 10 लाख का जुर्माना लगा रहे हैं।

?जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती।

वन रैंक वन पेंशन योजजा के तहत स्थाई कैप्टन को देय पेंशन के बारे में अभीतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि कितने साल तक ऐसा ही चलता रहेगा?

कोर्ट ने कहा, ?वे रिटायर कैप्टन हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। उनकी सरकार तक इन लोगों तक कोई पहुंच नहीं है ?या तो सरकार 10ङ अधिक भुगतान करना शुरू करें या जितना बनता है उतना भुगतान करें। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप अपना विकल्प चुनें।

एक और ट्रेन हादसा : झारखंड में ट्रैक पर डिब्बों से टकराई यात्री ट्रेन, दो की मौत, 150 घायल

नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश में एक के बाद एक हो रहे रेल हादसे ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। इसी बीच अब मंगलवार को झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा-सीएसएमटी मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस ट्रेन हादसे में दो लोगों की मौत की जानकारी मिली है जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई के रुट बदल दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक यह हादसा हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर चक्रधरपुर के पास हुई। बताया जा रहा है कि यहीं पर दो दिन पहले एक माल गाड़ी डिरेल हुई थी, जिसके वैगन ट्रैक पर ही पड़े थे। वहीं, हावड़ा-मुंबई मेल दूसरे ट्रैक से आ रही थी और पहले से ट्रैक पर पड़े डिब्बों से टकरा गई।

रेलवे की ओर से हावड़ा-मुम्बई रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। टाटानगर व चक्रधरपुर स्टेशन से रिलीफ ट्रेन और घटना की जांच के लिए इंजीनियरिंग विभाग की टीम को रवाना कर दिया गया है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। घायल यात्रियों को रांची के रिम्स हॉस्पिटल और चक्रधरपुर के आसपास के अस्पतालों में भर्मी कराया गया है।

राहुल गांधी हैं आक्रामक......मोदी सरकार नहीं दे पा रही जबाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के द्वारा मोदी सरकार को सदन में जमकर घेराव किया। बजट, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी हैं, इसमें दलित व आदिवासी एक भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधकर कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है। पीएम के विश्वास को इंडिया गठबंधन ने हिला दिया। मेरे भाषण में अब वे कभी नहीं आएंगे।

राहुल गांधी ने बजट से पहले की हलवा रस्म का हवाला देकर आरोप लगाया कि इस सरकार में दो-तीन प्रतिशत लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं और शेष हिंदुस्तान को यह नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बजट के बाद देश का मिडिल क्लास भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक मौका भी है।

राहुल गांधी के भाषण पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राहुल के तेवर जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और सत्ता पक्ष उतनी तीव्रता से उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा है, ये भारत की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए बड़ा संकेत है। राहुल जिस तरह से भाजपा सरकार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उससे इतना तय है कि मोदी सरकार 2014 या 2019 जैसे रंग में जवाब नहीं दे पा रही है। इसके पीछे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार जैसी उम्मीद से काफी पीछे रह जाना भी है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा

लोकसभा चुनाव में जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज्यादा गिन लिए गए

नई दिल्ली (ईएमएस)। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावा किया है कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, हाल के लोकसभा चुनावों में 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रमाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। हालांकि, एडीआर ने यह नहीं बताया कि वोटों के इस अंतर से कितनी सीटों पर अलग नतीजे आए।

चुनाव आयोग उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उसने वोटों की गिनती पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों किए। ईवीएम में पड़े वोटों, उनकी गिनती में अंतर, चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि, बूथ वाइज डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना, डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने पर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। एडीआर के फाउंडर जगदीप छोकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावों में देखे गए कई उल्लंघनों, अवैधताओं और अनियमितताओं की गंभीर घटनाओं को निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 में दोहराये जाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा है। इससे मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो गया है। इन आशंकाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके समाधान के प्रयास होने चाहिए।

538 सीटों पर डाले गए और गिने गए मतों में अंतर मिला

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा करते समय डाले गए और गिने गए वोटों में अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोडक़र 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विसंगतियां दिखाई दीं। सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई थी। इस तरह 538 संसदीय सीटों पर डाले गए और गिने गए मतों में 589691 का अंतर है।

लोकसभा चुनावों के पहले 6 चरणों में कोई विसंगी नहीं

पूनम अग्रवाल ने कहा कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय मुझे बिल्कुल यही परिणाम मिला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले 6 चरणों के लिए, ईसीआई के वोटर टर्नआउट ऐप ने मतदाताओं की सटीक संख्या प्रदर्शित की। हालांकि, अंतिम यानी 7वें चरण में इस ऐप पर डाले गए वोटों के आंकड़े सिर्फ प्रतिशत में दिए गए और पिछला डेटा हटा दिया गया।

2019 में पड़े और गिने गए वोटों में था 739104 का अंतर

विशेषज्ञों और एडीआर की टीम द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर किए गए रिसर्च के अनुसार, 542 निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण में 347 सीटों पर विसंगतियां दिखाई दी थीं। 195 सीटों पर कोई भी विसंगति नहीं थी। ये विसंगतियां 1 वोट (न्यूनतम) से लेकर 101323 वोट यानी कुल पड़े वोटों का 10.49 प्रतिशत (उच्चतम) तक थीं। 6 सीटें ऐसी थीं जहां डाले गए वोटों और गिने गए वोटों का अंतर जीत के अंतर से ज्यादा था। कुल मिलाकर डाले गए और गिने गए वोटों में 739104 का अंतर था।

आर्मी लैंड स्कैम मामले में आईएएस छवि को कोर्ट से झटका-सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने रांची में सेना की जमीन की बिक्री से जुड़े एक मामले में तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की युगल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, वह पिछले वर्ष अक्टूबर में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

गौरतलब है कि रांची के बरैतू इलाके में सेना की 4.55 एकड़ जमीन को बेचने में कथित रूप से संलिप्तता के लिए 04 मई को शहर में कई जगह छापेमार कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। यहां बताते चलें कि छवि रंजन 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। इससे पहले वो राज्य समाज कल्याण विभाग में निदेशक रहे हैं।

करोड़ों के हैं भूखंड

इस जमीन का बाजार मूल्य 161.64 करोड़ रुपये बताया गया है। ईडी ने पिछले माह ही कहा था कि रांची में चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम स्थित तीन भूखंडों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है, जिन भूखंडों का बाजार मूल्य 161.64 करोड़ रुपये है। इसी के साथ ईडी ने यह भी कहा कि इन भूखंडों को 'भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया को धोखाधड़ी करते हुए बेच दिया गया। ईडी का आरोप है कि झारखंड में भू-माफिया का एक गिरोह काम कर रहा है, जो कि भूमि के स्वामित्व को अवैध तरीके से हासिल कर लेता है।

यहां बताते चलें कि पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने निर्धारित समय में आरोपपत्र दायर नहीं करने के आधार पर जमानत याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। इस पर न्यायालय का कहना था कि जांच एजेंसी की ओर से जांच को पूरा करने में कोई विसंगति नहीं की गई है और एक आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, ऐसे में इस आधार पर जमानत दिए जाने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

उत्तरकाशी में फटे बादल, दर्जनों नहरें बहने से कई खेत बर्बाद, घरों में घुसा पानी

देहरादून,(ईएमएस)। उत्तरकाशी में बादल फटने से नाकुरी गाड़ के बरसाली क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। सिंगोट में लोगों के खेत बर्बाद हो गए। घरों में पानी भर गया है। सुरक्षा दीवार बह जाने से गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। सोमवार रात को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से ग्रामसभा सिंगोट, ग्रामसभा मांगली सेरा, ग्रामसभा बरसाली के नाकुरी में काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों के शौचालय, छानिया और घर क्षतिग्रस्त हो गए। दर्जनों नहरें बाढ़ में बह जाने से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है।

मौसम विभाग की ओर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है अन्य जिलों में भी तेज गजर के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

राज्य में 131 मार्ग बंद हैं। इसमें सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ और चमोली जिला प्रभावित हैं। पिथौरागढ़ जिले में दो बार्डर रोड और 21 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। चमोली में 23 ग्रामीण मार्ग प्रभावित हैं। बागेश्वर में एक जिला मार्ग, दो मुख्य जिला मार्ग और 13 ग्रामीण मार्ग, उत्तरकाशी में एक राज्य मार्ग, एक मुख्य जिला मार्ग और सात ग्रामीण मोटर मार्ग और देहरादून में दो राज्य मार्ग, एक अन्य मार्ग और 15 ग्रामीण मार्ग बंद हैं।

कारखानों में अब 12 घंटे तक काम करेंगे श्रमिक

श्रम मंत्री ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 विधानसभा में पुरस्थापित किया, एक सप्ताह में 48 घंटे तक ही काम करा सकेंगे

लखनऊ (ईएमएस)। प्रदेश में स्थित कारखानों में अब श्रमिकों से प्रतिदिन नौ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक काम कराया जा सकेगा। लेकिन कारखाना मालिक निर्धारित मजदूरी पर एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करा सकेंगे। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को विधानसभा में कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 पुरस्थापित किया। अनिल राजभर के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की बनाने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

वर्तमान में किसी कारखाना में श्रमिक से प्रतिदिन निर्धारित मजदूरी पर अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है। कानून में संशोधन के बाद श्रमिक से कारखाना में 12 घंटे काम कराया जा सकेगा, इसमें विश्राम के घंटे भी शामिल होंगे। लेकिन श्रमिक से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। इससे अधिक अवधि तक काम कराने पर श्रमिक को साधारण दर से दोगुनी दर से मजदूरी देनी होगी। महिला श्रमिकों से भी कारखानों में रात्रि पाली में कार्य कराया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले महिला श्रमिक की लिखित सहमति लेनी होगी। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की शर्तों का पालन भी करना होगा।

एक्शन में कोटा नगर निगम........बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद कराया

दिल्ली हादसे के बाद कोचिंग हब में हुआ एक्शन

कोटा (ईएमएस)। राजस्थान के कोटा में कोचिंग हब इलाकों में बिल्डिंगों के बेसमेंट में गैरकानूनी तरीके से लाइब्रेरी, मिनी थिएटर, मेस और गेम जोन चलाए जा रहे थे। दिल्ली में हुए हादसे के बाद नगर निगम ने कार्रवाई कर इन बेसमेंट की जांच कर 13 लाइब्रेरी को बंद करवा दिया।

कोटा नगर निगम ने दिल्ली हादसे के बाद कोचिंग हब इलाकों में बनी बिल्डिंगों के बेसमेंट की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि भवन मालिक ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बेसमेंट में नियमों के विरुद्ध कई तरह के कामकाज करवा रहे हैं।

निगम अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे कामों के लिए। नगर निगम के संयुक्त चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने कहा, बेसमेंट की जगह सिर्फ पार्किंग के उपयोग के लिए है ना कि दूसरे उपयोग के लिए। उन्होंने चेतावनी देकर कहा, कोई लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती हुई मिली, तब एक्शन होगा।

कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए हजारों छात्र आते हैं। जिन छात्रों के पास पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं होता, वे लाइब्रेरी का रुख करते हैं। कोटा में 100 से भी ज्यादा लाइब्रेरी चल रही हैं, जिसमें ज्यादा तर बेसमेंट में हैं।

एक अनुमान के मुताबिक कोटा में 100 से ज्यादा लाइब्रेरी चल रही हैं और इनमें से ज्यादा तर बेसमेंट में संचालित हैं। लाइब्रेरी में छात्रों को इंटरनेट, वाई-फाई, एसी, पंखे, लाइट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। छात्रों से 600 से लेकर 1000 रुपये प्रति महीना तक फीस ली जाती है।

जन हितैषी

538 लोकसभा सीटों पर पड़े वोट और गिने गए वोटों पर अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। 362 लोकसभा की सीटों पर मतदाताओं द्वारा डाले गए और गिने गए वोटो में 5,54,598 वोटो का अंतर है। मतगणना कम वोटों की की गई है। जबकि जीतने वाले प्रत्याशी और दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। इससे जीत-हार प्रभावित हुई है। लोकसभा की 176 लोकसभा सीटों पर वोट कम पड़े और 35093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। 538 सीटों पर कुल वोटों का अंतर 5,89,691 पाया गया है। इस संस्था के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदान का डाटा जारी करने में भी पारिदर्शिता नहीं बरती गई है। चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के आंकड़े काफी विलंब से जारी किए गए। प्रारंभिक मतदान और अंतिम मतदान के परिणामों में 5 करोड़ से अधिक वोटों का अंतर पाया गया है। अभी भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना के आंकड़े मतदान केंद्र के हिसाब से जारी नहीं किए गए हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना को लेकर संदेह बना हुआ है। जबकि यह जानकारी पूर्व में चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही थी। एडीआर ने 79 लोकसभा सीटों का एक अलग विश्लेषण जारी किया है। जिसमें मतदान कम होने की जानकारी दी गई थी। जब मतगणना हुई, उसमें करोडों वोट ज्यादा गिने गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के बीच में आदर्श आचार संहिता की जो शिकायतें की गई थीं, उन पर भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा शिकायतों का भेदभाव पूर्ण ढंग से निपटारा करने का आरोप लगा है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार पक्षपात और संदेह व्यक्त किया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायाधीश, वकील और पत्रकार भी शामिल हैं। यह संस्था पिछले कई वर्षों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का डाटा इकट्ठा करती आ रही है। उसका विश्लेषण करती है, और समय-समय पर वह डाटा सार्वजनिक पोर्टल पर जारी करती है। इस संस्था की बड़ी विश्वसनीयता मतदाताओं, मीडिया और संस्थाओं के बीच में बनी हुई है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध डाटा के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए गड़बड़ियों को उजागर करती है। समय-समय पर इस संस्था द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सकें, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करती है। 5 वर्ष पहले भी इस संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के कारण डिटेल में जाकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में ईवीएम मशीन, बीवीपेट मशीन, बीवीपेट से निकली हुई मतदान पर्चियों की गिनती, माइक्रोकंट्रोल यूनिट इत्यादि के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किए थे, उसका पालन भी चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत नहीं किया गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था। उसको बदलते हुए सरकार ने एक नया कानून बनाया। जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, और नेता प्रतिपक्ष के तीन सदस्यों की कमेटी ने चुनाव के ठीक पहले तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। यह नियुक्ति भी विवादों में है। नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों ने शपथ भी ले ली है। सरकार का गठन भी हो गया है। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। संगठन ने चुनाव आयोग से भी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देने के स्थान पर छुपाया जा रहा है। इससे भी संदेह बढ़ रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदान की जानकारी शाम को 7 बजे और दूसरे दिन दोपहर 11 बजे तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है। उसको मतदान केंद्र के हिसाब से जारी कर देती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा जो प्रारंभिक मतदान की जानकारी दी गई थी। उसके कई दिनों बाद मतदान के जो आंकड़े जारी किए गए, उनमें करोडों वोटो का अंतर है। राज्यवार 12 फ़ीसदी तक का अंतर मतदान में है। निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अभी तक मतदान केंद्र के मतगणना का आंकड़ा मतदान केंद्रों के हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा पोर्टल पर नहीं डाला गया है। एक निश्चित समय पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव याचिका हाईकोर्ट में दायर करनी पड़ती है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, निर्वाचन क्षेत्र का दूसरे नंबर का उम्मीदवार यदि मतगणना से सहमत नहीं है। वह राशि भरकर 45 दिन के अंदर जांच की मांग कर सकता है। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई नियम नहीं बनाए हैं। जिन पराजित उम्मीदवारों ने आवेदन लगाए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है। भारतीय लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद मतदान पर ही रखी गई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। मतदाताओं से मिले हुए इस अधिकार से केंद्र एवं राज्य सरकार का गठन होता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें जनता के लिए कानून बनाती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसी के अनुसार काम करती हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसको निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है। चुनाव आयोग, चुनाव की निष्पक्षता, पारिदर्शिता और सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर मिलें। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलें। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की गई है। यदि मतदाताओं को चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं होगा? चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करेगा, तो लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी बिना डर और भय के सवाल कर सके। बिना किसी दबाव में आए काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कमेटी बनाई थी, उसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ना मानते हुए, जो कानून बनाया। उसमें तीन सदस्यों की कमेटी में दो सदस्य सरकार के और एक विपक्ष का रखा गया। जिसके कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर, मतदान और मतगणना पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, जो प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर खड़े हुए हैं। उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करके, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। लोकतंत्र तथा संविधान मजबूत हो। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन आज भी सबसे सशक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान केंद्रीय चुनाव आयोग से भी अपेक्षा की जाती है। वह अपने संवैधानिक दायित्व को बिना किसी भय और पक्षपात के ईमानदारी से चुनाव कराएं।

शब्द पहेली - 8084

बाएँ से दाएँ

1. साले की पत्नी-4
3. उच्च कुल का -3
5. पाताल-4
8. व्यंग,चुटीली बात-2
10. दुख,कष्ट-2
11. शराब का प्याला-2
13. सत्य,तेज-2
14. जुड़वा-3
15. विश्राम,राहत-3
17. मक्का-मदीना की यात्रा-2
19. झुका हुआ-2
20. टैक्स,हाथ-2
21. होठ,अधर-2
23. सुरक्षित-4
25. नाश,विनाश,विध्वंस-3
26. निश्चित -4

ऊपर से नीचे

1. नदी-3
2. संपत्ति,धन-2
3. वंश,खानदान-2
4. उत्तमता,परिष्कृतता-4
6. समुद्र,दरिया-3
7. अंधकार-2
9. जो जायज न हो-4
12. संस्कृत में 'मेरा'-2
13. सपाट- 4
16. जांघ-2
17. पैगंबर,महापुरुष-4
18. रनिवास (उर्दू-3)
20. हुनर,फन-2
22. देह,काया-3
23. गलत का विलोम -2
24. निश्चित-2

शब्द पहेली - 8083 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

लोकसभा 45 मिनिट का चक्रव्यूह और राजनीति

चक्रव्यूह महाभारत के समय का हो या कलियुग का खतरनाक होता है। कलियुग की बल्कि मोदी युग की सियासत कमलाकार चक्रव्यूह में फंसी है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 45 मिनिट तक मौजूदा सियासी चक्रव्यूह पर जब लगातार बोला तो सत्तापक्ष के हौसले कमजोर होते दिखाई दिए। लोकसभा अध्यक्ष तक राहुल गांधी के सामने असहाय नजर आये।

पिछले एक दशक में लोकसभा का सोमवार का दिन सबसे जायदा मार्मिक था। किसी को अंदाज नहीं था कि बजट भाषण पर बोलते हुए प्रतिपक्ष को इस हिकमत अमली के साथ बेनकाब करेंगे ,की सत्तापक्ष मन मसोस कर रह गया। सत्ता के बचाव में खड़े देश के रक्षा मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री तक दांत पीसते नजर आये लेकिन राहुल को बोलने से नहीं रोक पाए।सत्ता पक्ष को भी ये उम्मीद नहीं थे कि विपक्ष के नेता उनके ही तीर से उन्हें ही भेदने में कामयाब हो जायेंगे। देश ने पहली बार देखा की लोकतंत्र की भूमि अभी वीरविहीन नहीं हुई है। राहुल कि भाषण कि दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सबने बिलबिलाते देखा। किरण ने राहुल पर आरोप लगाया कि वे संसदीय कानूनों को नहीं जानते। किरण ये आरोप लागते हुए भूल जाते हैं कि राहुल उतने ही वरिष्ठ संसद हैं जितने की वे। राहुल गांधी को संसदीय कामकाज का ज्ञान नहीं होगा। राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी वरिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री से भी। उन्हें यदि संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान न होता तो ओम बिरला राहुल की गिल्लियां उड़ा देते।

राहुल कि भाषण में सच कितना था और झूठ कितना ये संसदीय अभिलेख में दर्ज हो चुका है। सत्तापक्ष चाहे तो उनके झूठ को बिना मशीन कि इस्तेमाल के भी जांचा जा सकता है। राहुल बच्चे नहीं है। उन्होंने अपना भाषण मेहनत से तैयार किया होगा ,तभी तो वे सत्तापक्ष के चक्रव्यूह को भेद सके और लगातार हमलावर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर अडानी और अम्बानी को भी निशाने पर लिया। सत्तापक्ष और लोकसभा अध्यक्ष भी राहुल को न रोक पाए और न टोक पाए,क्योंकि राहुल पूरी तैयारी से लोकसभा में आये थे। उन्होंने कराधान से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर जमकर बोला। उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कलियुग के उन पात्रों का भी उल्लेख कर दिया जो जनता के साथ लगातार गलत बयानी कर रहे हैं।

राहुल के भाषण में मोदी जी के भाषणों जैसे कटाक्ष नहीं थे। घबड़ाहट नहीं थी और न ही खिसियाहट। राहुल सामन्य होकर भाषण दे रहे थे। ये उनका आत्मबल है ,अन्यथा आज के युग में मोदी जी के मुकाबले कौन खड़ा हो सकता है ? राहुल ने देश में और भाजपा में व्याप्त भय को रेखांकित करना नहीं भूले । उन्होंने बार-बार इस बात का जिक्र किया कि भाजपा भय की राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा और उसके समर्थकों को शिवजी की बारात तक कह दिया। उन्होंने अपने भाषण में कोई भी मुद्दा नहीं छोडा । राहुल ने अग्निवीर,नीट पर्चा लीक हीनहीं बल्कि किसानों और युवाओं के भी मुद्दे उठाये। उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा भी छोड़ा नहीं है

देश ने देखा की राहुल के भाषण के समय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी भी सदन में मौजूद थीं ,लेकिन वे भी राहुल के बहशें के दौरान अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छिपातीं नजर आयी। वे या तो राहुल के भाषण से ऊब रहीं थीं या फिर शर्मसार हो रहीं थीं वित्तमंत्री जी की अकुलाहट देखने लायक थी। राहुल ने किसानों का ही नहीं अपितु पत्रकारों को एक शीशे के पीछे कैद किये जाने का भी जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष राहुल के आरोपों पर निरुत्तर दिखाई दिए। उन्हें न जानें कितनी बार राहुल को डांटा,डराया,धमकाया लेकिन जब राहुल पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ तो खामोश हो गए। राहुल ने जिस हिकमत अमली का मुजाहिरा किया वो अप्रत्याशित था। उन्हें जब लोकसभा अध्यक्ष ने हद में रहने और अडानी तथा अम्बानी पर बोलने से रोका तो राहुल ने एक को ऐ-वन और दूसरे को ऐ-टू के नाम से सम्बोधित करने की अनुमति मांगी।

गौरतलब है कि नयी लोकसभा में चुनकर आये विपक्ष के सदस्य गूंगे-बहरे नहीं है। राहुल से पहले तृण मूल कांग्रेस के अभिजीति बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को छकाया था। अभिजीत के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य कसमसाते रह गए। मुझे हैरानी है किलोकसभा अध्यक्ष ने इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक सदन के किसी सदस्य को निलंबित नहीं किया है। पिछली बार निलंबित सदस्यों की संख्या 150 के आसपास पहुंच गयी थी। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को असहाय देखकर मुझे उनसे विशेष सहानुभूति हुई ह। वे भले ही भाजपा से हैं इससे क्या फर्क पड़ता है ?

भाजपा के चक्रव्यूह में देश भी है और राहुल गांधी भी। अब देखना ये है की देश और राहुल भाजपा के इस चक्रव्यूह को भेद पाते हैं या उनकी दशा भी अभिमन्यु की तरह होगी ? आज की पीढ़ी महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में यदि नहीं जानती हो तो उसे गूगल खंगाल लेना चाहिए। समझ में आ जाएगा की अभिमन्यु वध में किसने ,क्या किया था। आज की भारतीय राजनीति में राहुल चक्रव्यूह में घिरे भी हैं लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह से निकलकर भी दिखा दिया है। राहुल मोदी युग में मोदी के रहते हुए भी अब एक ब्रांड बन गए हैं। यही उनकी उपलब्धि है। याद रखिये की मै न मोदी के पाले में हूँ और न राहुल के पाले में। मै जनता के पाले में हूँ। (लेखक राकेश अचल / ईएमएस)

मौत बांटते असुरक्षित कोचिंग सैंटर, पीजी और हॉस्टल

दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत-हादसे ने समूचे राष्ट्र को दुःखी एवं आहत किया है, यह हादसा नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, लापरवाही एवं लोभ की पराकाष्ठा है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर दोषग्रस्त कोचिंग प्रणाली और व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। इस दुःखद एवं पीड़ादायक घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। जिसकी कीमत निर्दोषों को अपनी जान गंवा का चुकानी पड़ रही है। निश्चित ही देशभर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए कोचिंग सैंटर डैथ सैंटर बन चुके हैं। कोचिंग सैंटरों का कारोबार शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। छात्रों को सुनहरी भविष्य का सपना दिखा कर मौत बांटी जा रही है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। प्रश्न है कि सैंटर के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन ऐसी घटनाओं के दोषी अधिकारी क्यों नहीं गिरफ्तार होते?

शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के कोचिंग सैंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डोल्विन, तान्य सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खड़ा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आईएएस की तैयारी कर रहा था और वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव ने अभी एक महीना पहले ही इस कोचिंग सैंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जहां 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। हादसे के वक्त 35 छात्र मौजूद थे। चंद मिनटों में ही बेसमेंट में पानी भर गया। सिर्फ इसी सैंटर में नहीं, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। जिसके गेट बायोमेट्रिक आईडी से खुलते हैं, जैसे ही बारिश होती है, बिजली चली जाती है, उसके बाद बेसमेंट से निकलना बिना बायोमैट्रिक आईडेंटिफिकेशन के मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हादसे और मौत की संभावना बढ़ जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर के न सिर्फ कोचिंग सैंटर बल्कि पीजी और हॉस्टल की असुरक्षित हालत भी मौत लिये किसी भी क्षण बड़े हादसे की संभावना के साथ खड़ी है। जहां इस कदर अवैध निर्माण है कि कभी भी दूसरा या दोबारा हादसा हो सकता है। इसलिये ऐसे हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला।

विडम्बनापूर्ण है ऐसे जलभराव एवं आगजनी के हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है। राजधानी में रह-रह कर एक के बाद एक हो रहे हादसों के बावजूद दिल्ली-सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक एम्यूजमेंट पार्क के अंदर गेमिंग जोन में लगी आग की लपटें हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बच्चों के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगना और अब कोचिंग सैंटर में तीन होनहार एवं देश के भविष्य बच्चों का दर्दनाक तरीके से डूबकर मर जाना-निश्चित रूप से ये हादसे प्रशासनिक लापरवाही की उपज हैं, यही कारण है कि सिस्टम में खामियों और ऐसी आपदाओं को रोकने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की निंदा भी व्यापक स्तर की जा रही है। यह याद रखने योग्य है कि नियमित अंतराल पर मानवीय जिम्मेदारी वाले पहलू की अनदेखी से ऐसी गंभीर घटनाएं होने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही कम होती नहीं दिख रही है। इन त्रासद हादसों ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए।

परिवार वालों ने और छात्रों ने स्वर्णिम भविष्य के सपने संजो कर और लाखों की फीस देकर कोचिंग शुरू की होगी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। छात्रों की मौत को महज हादसा नहीं माना जा सकता, यह एक तरह से निर्मम हत्या है और हत्यारा है हमारा सिस्टम। हादसे से आक्रोशित छात्रों का कहना है कि वे 10-12 दिन से दिल्ली नगर निगम से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई कारवाई जाए लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हादसे तभी होते हैं जब नियमों और कानूनों को ताक पर रखा जाता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलते ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। जलभराव क्यों और कैसे हुआ, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन इन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को उसके मालिकों ने मौत का कुआं बना रखा था। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है। हर दुर्घटना में गलती भ्रष्ट आदमी यानी अधिकारी एवं व्यवसायी की ही होती है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद ही उन पर कार्रवाई क्यों होती है? सरकार पहले क्यों नहीं जागती?

वैसे तो बेसमेंट में कोचिंग सैन्टर या लाइब्रेरी चलाना गैर-कानूनी है, इस घटना के सन्दर्भ जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। जलभराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 30-35 छात्र थे। यह तो गनीमत रही कि तीन अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे-तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जलभराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एमसीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ-साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है।

बात हम नया भारत एवं विकसित भारत की करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं बनी है और हम अनियंत्रित एवं असुरक्षित विकास करते जा रहे हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, चैन्नई या बेंगलुरु या ऐसे ही अन्य बड़े शहर -हर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। दिल्ली के इनकम टैक्स भवन में आग से एक अधिकारी की जान हाल में गयी। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक हैं या निर्दोषों को परेशानी करने के लिये है। औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े-बड़े दावे करने और उन्हें संवारने की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त एवं असुरक्षित हैं। हर हादसे पर सियासत होती है लेकिन कोचिंग सैंटर माफिया इतना ताकवर है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा क्यों है यह सब जानते हैं। (लेखक- ललित गर्ग)

आत्मविश्वास जगाकर आगे बढ़ें

वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में महानता की अनन्त सम्भावनाएँ छिपी पड़ी हैं। किंतु मनुष्य को अपनी महत्ता पहचानकर उसके अनुरुप चिन्तन और कर्म भी तो करना चाहिए। कोई मनुष्य किसी एक दिशा में महान् हो सकता है तो कोई अन्य मनुष्य किसी दूसरी दिशा में आगे बढ़ सकता है। जिस मनुष्य के पास जो कुछ गुण या शक्ति है, वह उसी को लेकर ऊँचा उठे। तभी उसकी सफलता और सार्थकता है। अनन्त शक्तिमान् परमेश्वर का अंशभूत होने के कारण मनुष्य में अनन्त शक्तियों का भण्डार भरा पड़ा है तथा उसमें अनन्त उन्नति की सम्भावनाएं छिपी हुई हैं। अपनी निधि को बिना पहचाने तो राजा भी रंक ही है। मनुष्य अपनी अगणित प्रसुप्त शक्तियों को भूलकर दयनीय और उन्हें जगाकर समर्थ हो जाता है। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है, उनके सदुपयोग करने और संकल्प लेने की आवश्यकता है, उत्तम लक्ष्यों की ओर चल पड़ने की आवश्यकता है, दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मनुष्य को कभी-कभी एकान्त में बैठकर आत्मविश्वास को जगाने का अभ्यास करना चाहिए और पग-पग पर सँभलने का निश्चय करना चाहिए। मनुष्य आत्मविश्वास को जगाकर ही संकटों को पार करता हुआ आगे बढ़ सकता है, ऊँचे उठ सकता है और महान् बन सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ हैं अपनी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की अपनी सामर्थ्य में विश्वास होना। मनुष्य विवेक के सहारे अपने विलुप्त आत्मविश्वास को जगा सकता है।हमारे विचारों, आशाओं, निराशाओं, भय, घृणा, क्रोध आदि मनोवेगों का प्रभाव हमारे शरीर के अंग-प्रत्यंग पर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य और मनोदशा पर पड़ रहा है, शरीर की एक-एक कोशिश (सेल) पर पड़ रहा है ; हृदय और मस्तिष्क पर पड़ रहा है, रक्त पर पड़ रहा है, स्नायुतंत्र (नर्वस-सिस्टम) पर पड़ रहा है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में झलक रहा है। जितनी बार भी हम चिंता से घबरा उठते हैं अथवा उत्तेजित होकर व्यर्थ ही घृणापूर्ण क्रोध में भड़क उठते हैं, उतनी बार हम मानों अपने ही शरीर में, मस्तिष्क से तथा प्रत्येक सेल से ही लड़ बैठते हैं। प्रत्येक चिन्ता और भय हमारे मन और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़कर जाते हैं। चिंता और भय हमारे स्नायु-तंत्र में कम्पन तथा रक्त में एक विषैला तत्व उत्पन्न कर देते हैं जो हमें जर्जर कर देते हैं। मानसिक तनाव से बृहदांत्र शोथ (कोलाइटिस), उदरव्रण, सिरदर्द, कमरदर्द, हृदयघात आदि महारोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक तनाव का उपाय आत्मविश्वास ही तो है। आत्मविश्वास जगाकर आगे बढ़ें। सब लोग आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ते हैं अतएव किसी व्यक्ति का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा देना उसकी सबसे बड़ी सेवा एवं सहायता है। हताश होना अथवा हताश करना अक्षम्य अपराध है। जहाँ आत्मविश्वास है तथा प्रभु पर विश्वास है, वहाँ चिन्ता और भय न रह सकेंगे। भक्तिभाव से ओत-प्रोत होकर कबीर कहते हैंः

उस समरथ को दास हौं, कदै न होय अकाज।
पतिबरता नांगी रहै, वाही पुरुस को लाज॥

ईश्वरभक्त का विश्वास है कि उसका अकाज नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है, किंतु यदि कुछ हानि हो भी जाय तो वह ईश्वर का ही प्रसाद है। ईश्वर-विश्वास के प्रकाश में चिंता का अन्धकार लुप्त हो जाता है। धीरे-धीरे मस्ती को स्वभाव का अंग बना लें। मस्ती की आदत डाल लें। मस्त स्वभाव के बिना आप छोटी-छोटी बातों पर बड़ी चिन्ता करने लगेंगे, चिड़चिड़े होकर लड़ने लेगेंगे, दुःखी रहने लगेंगे और रक्तचाप आदि के शिकार हो जायेंगे। कुछ लोग छोटी-सी मिट्टी की बमी पर ऐसे चढ़ते हैं, जैसे पर्वत पर चढ़ रहे हों। छोटी-सी बात पर ऐसी चिन्ता करते हैं, जैसे घोर संकट आ गया हो। मस्ती, प्रभु के प्रति भक्ति और मनुष्यों के प्रति अथाह प्रेम जगाने से स्वयं आविर्भूत हो जाती है।व्यर्थ ही निरन्तर गम्भीरता, गारिमा का भारी बोझ सिर पर उठाये हुए हम खिलखिलाकर हँसना भूल गये तथा बात-बात पर चिढ़ने लगे। चिढ़ानेवाला व्यक्ति दुष्ट और चिढ़नेवाला मूर्ख होता है। छोड़ो, छोड़ो चिढ़ना और चिढ़ाना। अपना लो हँसना और हँसाना। हास्य और विनोद को स्वभाव का अँग बना लो। कटुता का उत्तर मधुर भाषा में देना सीखकर आगे बढ़ें। (लेखक-संजय गोस्वामी / ईएमएस)

सम्पादकीय

खेल-समाचार

भारत और बांग्लादेश करेंगे 2025 और 2027 में एशिया कप का आयोजन : एसीसी

कुआलालंपुर (ईएमएस)। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने कहा है कि भारत में साल 2025 में टी20 एशिया कप खेला जाएगा। एसीसी के अनुसार एशिया कप को हमेशा वैश्विक आयोजन की तैयारियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसी प्रारूप में खेला जाता है। एशिया कप के 2023 सत्र की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 'हाईब्रिड मॉडल पर की थी। भारत ने तब एशिया कप के लिए पाक का दौरा करने से मना कर दिया था और इसके ज्यादातर मैच श्रीलंका में खेले गए थे। बांग्लादेश साल 2027 में एकदिवसीय प्रारूप में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय विश्व कप खेला जाना है। भारत में टी20 प्रारूप और बांग्लादेश में 50 ओवर के प्रारूप में खेले जाने वाले एशिया कप में 13-13 मैच खेले जाएंगे। एसीसी ने कहा कि पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट एसीसी द्वारा नामित सदस्यों के बीच दो साल के अंतराल पर आयोजित होने वाला पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट है।

पेरिस ओलंपिक : भारतीय हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया, ग्रुप में शीर्ष पर पहुंची

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने मंगलवार को आयरलैंड को 2-0 से हराया। इसी के साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गयी है। भारतीय टीम की ओर से ये दोनो गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 11 वें और 19 वें मिनट में किये। भारतीय टीम ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था जबकि उसका दूसरा मैच अर्जेंटीना से 1-1 से बराबरी पर रहा था। वहीं तीसरे मैच में उसने 2-0 से आयरलैंड के खिलाफ आसान जीत दर्ज की है।

भारत ने आयरलैंड के खिलाफ अच्छी शुरुआत की। भारतीय टीम ने दूसरे ही मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया पर हरमनप्रीत इसे गोल में बदल नहीं पाये। भारत की ओर से पहला गोल पहले क्वार्टर के 11 मिनट में करने में हरमनप्रीत सफल रहे ओर इस प्रकार टीम को 1-0 से बढ़त मिल गयी। 11 वें मिनट में आयरिश रक्षापंक्ति ने भारतीय खिलाड़ी को गिरा दिया पर पर भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला जिसे गोल में बदलने में हरमनप्रीत ने कोई गलती नहीं की। इसके बाद विरोधी टीम ने बराबरी के प्रयास किये पर वह सफल नहीं हुई।

भारत ने दूसरे क्वार्टर में शुरुआत से ही हमले किए। उसने पहले 4 मिनट में ही तीन पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए और तीसरे पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में भी बदल दिया। 19 वें मिनट में ये गोल भी हरमनप्रीत ने ही किया। यह टूर्नामेंट में हरमनप्रीत का चौथा गोल है। आयरलैंड ने वापसी के जमकर प्रयास किये। उसने तीसरे क्वार्टर के आखिरी 3 मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए पर भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने उन्हें विफल कर दिया। आयरलैंड को 6 पेनाल्टी कॉर्नर मिले पर वह एक को भी गोल में बदल नहीं पाया।

पेरिस ओलंपिक : नौकायन की पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे बलराज

पेरिस (ईएमएस)। भारत के बलराज पंवार पेरिस ओलंपिक की नौकायन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गये हैं। बलराज ने नौकायन की पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत का एक और पदक तकरीबन पक्का कर दिया है। बलराज ने क्वार्टर फाइनल में 2000 मीटर की दूरी 7:05:10 का समय निकालकर पूरी की। उन्होंने पांचवें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब वह 13वें से 24वें स्थान के लिये खेलेंगे। इस स्पर्धा में चार क्वार्टर फाइनल हीट में शीर्ष तीन पर रहने वाले खिलाड़ी सेमीफाइनल ए-बी में पहुंचे और अब इनके बीच पदक के लिए मुकाबला होगा। बलराज क्वार्टर फाइनल में चौथी हीट में 5वें नंबर पर रहे। इससे पहले ये भारतीय खिलाड़ी रेपेचेज दौर की रेस में दूसरे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। वह शनिवार को पहले दौर की हीट रेस में चौथे स्थान पर रहकर रेपेचेज में पहुंचे थे।

वहीं इससे पहले बलराज ने रविवार को पुरुषों की एकल स्कल्स स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए रेपेचेज राउंड में 7:12.41 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने पहले 1000 मीटर की दूरी 03:33.94 में पूरी की और उस समय दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने मोनाको के क्वेंटिन एंटोगनेली को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस वर्ष दक्षिण कोरिया में एशियाई और ओसियन रोइंग ओलंपिक क्वालीफिकेशन रेगाटा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में प्रवेश हासिल किया था।

ओलंपिक में आज होने वाले भारत के मुकाबले

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी बुधवार को भी कई मुकाबलों में उतरेंगे। इसमें मुक्केबाज से लेकर टेबल टेनिस तक शामिल हैं।

31 जुलाई तीरंदाजी 15:30 से
बैडमिंटन 12:50 से
मुक्केबाजी (आर16)15:02 से
घुड़सवारी 13:30 से
रोइंग 13:24 से
निशानेबाजी (मेडल मैच) 13:24 से
टेबल टेनिस (आर 32) 13:30 से

पेरिस ओलंपिक में भारत 26 वें स्थान पर , जापान पहले और फ्रांस दूसरे नंबर पर

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में भारत को अब तक दो कांस्य पदक मिले हैं और ये दोनो ही निशानेबाज मनु भाकर के नाम हैं। मनु ने 10 मीटर पिस्टल में एक पदक जीतने के बाद दूसरा पदक मिश्रित टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ जीता है। इस प्रकार भारत के अब तक दो कांस्य पदक हो गये हैं। इसके बाद भी पदकों के मामले में भारत अभी भी 26वें स्थान पर है। वहीं (6 स्वर्ण , 2 रजत ओर 4 कांस्य के साथ ही कुल 12 पदकों के साथ जापान पहले स्थान पर है जबकि फ्रांस 5 स्वर्ण , 8 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ ही कुल 16 पदक के साथ ही दूसरे स्थान पर है जबकि चीन 5 स्वर्ण , 5 रजत और 2 कांस्य के साथ ही कुल 12 पदकों के साथ ही तालिका में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया 9-9 पदक के साथ ही चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। इन दोनो के ही 5-5 स्वर्ण हैं।

मोर्केल बन सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नये गेंदबाजी कोच

मुम्बई (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्नी मोर्केल को भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया जा सकता है। भारतीय टीम के नये मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से मोर्केल के नाम की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोर्केल बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से गेंदबाजी कोच की भूमिका संभालेंगे। उनकी आधिकारिक नियुक्ति सितंबर में टीम की घरेलू सीरीज से पहले होने की उम्मीद है। ऐसे में साईराज बहुतुले को मुख्य गेंदबाजी कोच के रूप में रखे जाने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बहुतुले अभी श्रीलंका में भारतीय टीम के साथ अंतरिम गेंदबाजी कोच के तौर पर गये हैं।

माना जा रहा है कि गंभीर और मोर्केल दोनों के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स में रहने के दौरान अच्छे संबंध हो गये थे। गंभीर ने दो साल तक सुपर जायंट्स के साथ मेंटर के रूप में काम किया था। गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल होने और मुख्य कोच एंडी फ्लावर के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में चले जाने के बाद मोर्केल नए मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ फ्रैंचाइजी के गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहे। गंभीर ने पहले भी बीसीसीआई से गेंदबाजी कोच के पद के लिए मोर्केल के नाम पर विचार करने का अनुरोध किया था। मोर्केल ने अपने करियर के दौरान साली 2006 से 2018 के बीच 86 टेस्ट, 117 एकदिवसीय और 44 टी20 मुकाबले खेले हैं।

पेरिस ओलंपिक में मनु, मनिका सहित भारतीय खिलाड़ियों ने बनाये रिकार्ड

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक पेरिस ओलंपिक में कई रिकार्ड अपने नाम किये हैं। निशानेबाजी में मनु भाकर, बैडमिंटन में सात्विक और चिराग और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने ये रिकार्ड बनाये हैं।

मनु भाकर ने यहां दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के साथ ही मिश्रित इवेंट में भी कांस्य पर निशाना लगाया। वहीं बैडमिंटन में युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मैच रद्द हो गया। इसके बाद इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले किसी भी भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन के युगल मुकाबले से क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बनायी थी।

ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना एक युग की शुरुआत होगा : द्रविड़

किसी भी भूमिका में शामिल रहना चाहूंगा

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच रहे राहुल द्रविड़ साल 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर उत्साहित हैं। द्रविड़ ने कहा कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना अभूतपूर्व उपलब्धि है। एक कार्यक्रम में उन्होंने इसे एक युग की शुरुआत बताया है। द्रविड़ ने ये भी कहा कि वह भी 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट के साथ किसी भी भूमिका में शामिल होना चाहेंगे।

द्रविड़ ने ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने पर कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि क्रिकेट को इसका हिस्सा होना चाहिए। यह वास्तव में एक महान खेल है। दुनिया भर में बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। यह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए शानदार है जो अब केवल एक प्रशंसक है। यह वास्तव में अभूतपूर्व है। द्रविड़ ने पूर्व अमेरिकी ट्रैक एवं फील्ड एथलीट कार्ल लुईस को टेलीविजन पर पदक जीतते हुए देखने की अपनी यादें ताजा की, जिनके नाम 9 ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं। द्रविड़ ने अमेरिका में क्रिकेट के प्रति जुनून के बारे में भी बताया और कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई।

द्रविड़ के साथ इस कार्यक्रम में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस, ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ और को-फाउंडर हर्ष जैन भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम इंडिया हाउस पार्क ऑफ नेशंस में पार्क डे ला विलेट में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान ये पहली बार है जब इंडिया हाउस की शुरुआत हुई है। पेरिस खेलों में इंडिया हाउस दुनिया भर के प्रशंसकों, वैश्विक खेल जगत के प्रमुख हितधारकों, भारतीय यात्रियों, मीडिया और एथलीटों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

सोना बढ़कर 68,738 रुपए, चांदी 81,523 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को सोने और चांदी के वायदा भाव में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के वायदा भाव 0.16 फीसदी की तेजी के साथ 68,738 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का वायदा भाव 0.29 फीसदी की बढ़त के साथ 81,523 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था। सोमवार को एमसीएक्स पर सोने के भाव 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 68565 पर और चांदी की कीमत 0.11 फीसदी गिरकर 81200 पर बंद हुई थी। सोने के वायदा भाव ने इस महीने 74,471 रुपए के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। इस साल चांदी के वायदा भाव ने 96,493 रुपए के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 950 रुपए की गिरावट के साथ 71,050 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी का भाव भी 4,500 रुपए औंधे मुंह लुढ़ककर 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। यह 2024 में चांदी की कीमतों में किसी एक कारोबारी दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले सत्र में यह 89,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों के कमजोर उठान के कारण चांदी में गिरावट आई। कारोबारियों ने कहा कि बाजार में आभूषण विक्रेताओं के साथ-साथ खुदरा लिवालों की मांग घटने से सोने की कीमतों में गिरावट आई।

बोपन्ना ने ओलंपिक में हार के साथ ही खेल से संन्यास लिया

पेरिस (ईएमएस)। भारत के सबसे अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ओलंपिक पुरुष युगल के पहले दौर में हार के बाद खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। 43 साल के बोपन्ना और उनके जोड़ीदार श्रीराम बालाजी की जोड़ी को फ्रांसीसी जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बोपन्ना ने कहा कि मैंने देश के लिए अपने करियर का अंतिम मैच खेल लिया है हालांकि मैं जीत के साथ अलविदा कहना चाहता था पर वैसा नहीं हो पाया। बोपन्ना और बालाजी को एडवर्ड रोजर वासेलिन और गेल मोनफिल्स की फ्रांसीसी जोड़ी ने 5-7, 2-6 से हराया था। इससे भारत के ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीदें फिर टूट गयी।

भारत की ओर से अंतिम बार पेस ने अटलांटा ओलंपिक के पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद से ही भारत अब तक कोई पदक नहीं जीत पाया है। बोपन्ना साल 2016 में सानिया मिर्जा के साथ मिश्रित युगल में पदक के करीब पहुंचे थे पर यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।बोपन्ना ने कहा कि वह 2026 एशियाई खेलों में शामिल नहीं होंगे और कहा कि ओलंपिक के साथ ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं अब जब खेल सकूंगा तब टेनिस का आनंद उठाउंगा। उन्होंने पहले ही डेविस कप से संन्यास की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दो दशकों तक भारत की ओर से खेलूंगा। मैंने 2002 में करियर की शुरुआत की थी और 22 साल बाद भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला ये मेरे लिए गर्व की बात है।

सेबी ने जारी की, 980 पंजीकृत कंपनियों की सूची

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, युटुब इत्यादि पर विज्ञापनों के माध्यम से ठगी की जा रही है। विज्ञापनो में मोटे मुनाफा का लालच देकर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। निवेश के लिए कई फर्जी वेबसाइट बनाई गई हैं। ठगी करने के बाद यह वेबसाइट बंद हो जाती हैं।

गृह मंत्रालय ने ठगी की इस कार्रवाई को रोकने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। जिसमें लोग यह जान सकेंगे, विज्ञापन में जो वेबसाइट बताई गई है। वह सही है या फर्जी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सेबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाली सभी 980 रजिस्टर कंपनियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। गृह मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है। वह ठगी से बचने के लिए वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कंपनियों की जानकारी प्राप्त करें।

शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से बाजार में उत्साह नहीं देखा गया। सुबह सेंसेक्स 112 अंक की गिरावट के साथ 81,243 जबकि निफ्टी 1.75 अंकों की मामूली तेजी के साथ 24,837 के स्तर पर खुला। प्री-ओपनिंग में बाजार हरे निशान पर था। दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 99.56 अंक तकरीबन 12 फीसदी बढ़कर 81,455 और 50 शेयरों वाला निफ्टी 21 अंक तकरीबन 0.09 फीसदी ऊपर आकर 24,857 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट रही। ऑयल एंड गैस कंपनी के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गयी।

प्री-ओपनिंग में बाजार लाभ पर रहा। सुबह सीमित दायरे में कामकाज हुआ। अमेरिकी बाजार में भी मिला-जुला कारोबार हुआ। डाओ जोंस 50 अंक नीचे आया जबकि नेसडेक और एसएंडपी 500 पर हल्की बढ़त दर्ज की गई। डाओ जोंस 0.12फीसदी गिरकर 40,539 पर बंद हुआ। नेसडेक 0.071 फीसदी की तेजी के साथ 17,370 के स्तर पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.081 फीसदी की तेजी रही।

वहीं एशियाई बाजार में आज गिरावट रही। जापान के निक्केई में 0.96 फीसदी और हॉन्गकॉन्ग के हैंगसेंग में 1.17फीसदी की गिरावट है। वहीं, चीन के शंघाई कंपोजिट 0.48फीसदी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गत दिवस 2,474.54 करोड़ के शेयर बेचे।

देश में बिजली उत्पादन क्षमता 10 साल में 80 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पिछले 10 साल में करीब 80 प्रतिशत बढ़कर जून 2024 तक 4,46,190 मेगावाट हो गई। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्च 2014 में स्थापित क्षमता 2,48,554 मेगावाट थी, जो जून, 2024 तक बढ़कर 4,46,190 मेगावाट हो गई। कोयला आधारित बिजली की स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 1,39,663 मेगावाट थी। इस साल जून में बढ़कर 2,10,969 मेगावाट हो गई। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 75,519 मेगावाट थी जो जून 2024 में 1,95,013 मेगावाट हो गई। मंत्री ने कहा कि भारत का ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड में से एक के रूप में उभरा है और पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ने से देश एक एकीकृत बिजली बाजार में बदल गया है।

सेबी भेदिया कारोबार नियम एक नवंबर से लागू करेगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। पूंजी बाजार नियामक सेबी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने के ?लिए भेदिया कारोबार नियम एक नवंबर से लागू करेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी की गयी है। एक अधकारी ने कहा ?कि सेबी ने मूल्य से संबद्ध अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किये जाने को अनिवार्य किया है। इसके जरिये सेबी भेदिया कारोबार को लेकर व्यवस्था का चाक-चौबंद बना रहा है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाये रखने और इसका लाभ उठाने को लेकर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने पर जोर भेदिया कारोबार को रोकने के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेबी की एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) (संशोधित) नियमन, 2022 एक नवंबर, 2024 से अमल में आएगा। निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दी है।

एक दिन बाद....1 अगस्त से होगा ये बदलाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। जुलाई का महीना खत्म होने के साथ अगस्त की शुरुआत हो रही है। महज एक दिन का समय बाकी है और उसके बाद 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव देखने में मिल सकते है। जो सीधे आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियमों में चेंज शामिल हैं।

ऑयल मार्केटिंग कंपनिया हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 अगस्त 2024 को सुबह छह बजे से संशोधित दाम जारी किए जा सकते हैं। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव हुए हैं, वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इसके बाद लोगों को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद है।

2. एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी-पीएनजी

देशभर में महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी के दाम भी संशोधित करती हैं। 1 अगस्त 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती हैं।

3. क्रेडिट कार्ड

निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए भी 1 अगस्त की तारीख बदलाव लेकर आ रही है। दरअसल, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए के भुगतान थर्ड पार्टी एप से किए जाएंगे, तब उस ट्रांजैक्शंस पर 1 प्रतिशत चार्ज लगाया जाएगा और प्रति ट्रांजैक्शंस लिमिट 3,000 रुपये तय की गई है। फ्यूल ट्रांजैक्शंस पर 15,000 रुपये से कम के लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, हालांकि, 15,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर कुल राशि पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

4. गूगल मैप के चार्ज

गूगल मैप भी 1 अगस्त 2024 से भारत में अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जो पहली तारीख से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। दरअसल, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने अपनी गूगल मैप सर्विस पर भारत में लिए जाने वाले शुल्क को 70 फीसदी तक कम करेगा। इसके अलावा अब गूगल अपनी मैप सर्विस का पेमेंट डॉलर की जगह भारतीय रुपये में भी लेगा।

5. 13 दिन बैंक बंद

अगस्त महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम हैं, तब घर से निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट पर नजर लें। दरअसल, अगस्त के पूरे महीने में 13 दिन बैंकों में काम-काज नहीं होगा। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे विभिन्न मौके के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को पड़ने वाला साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है।

स्लोवाकिया ने दी यूक्रेन को डीजल की आपूर्ति रोकने की धमकी

- यूक्रेन के माध्यम से स्लोवाकिया को लुकोइल से तेल की आपूर्ति पहले ही बंद हो चुकी है

प्राग (ईएमएस)। स्लोवाकिया ने कहा है कि अगर यूक्रेन के रास्ते स्लोवाकिया में रूसी तेल का पारगमन जल्द ही फिर से शुरू नहीं किया जाता है, तो स्लोवाक रिफाइनरी स्लोवनाफ्ट यूक्रेन को डीजल की आपूर्ति निलंबित कर देगी। गौरतलब है कि यूक्रेन ने हाल ही में रूसी कंपनी लुकोइल से ड्रुज़बा पाइपलाइन के माध्यम से स्लोवाकिया और हंगरी तक तेल के पारगमन को रोक दिया था। यूक्रेन ने ?पिछले जून महीने में कंपनी को अपनी प्रतिबंध सूची में डाल दिया था। इसके बाद स्लोवाकिया के वित्त मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन के माध्यम से स्लोवाकिया को लुकोइल से तेल की आपूर्ति पहले ही बंद हो चुकी है। स्लोवाकिया के के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने फेसबुक पर प्रकाशित एक वीडियो संदेश में कहा कि इस मूर्खतापूर्ण प्रतिबंध के आगे कार्यान्वयन से केवल यूक्रेन, स्लोवाकिया और हंगरी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा ?कि अगर यूक्रेन के माध्यम से रूसी तेल का पारगमन जल्द ही फिर से शुरू नहीं किया जाता है, तो स्लोवनाफ्ट यूक्रेन को डीजल की आपूर्ति बंद कर देगा। फिको ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान विवाद को हल करने के लिए अपने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल को एक तकनीकी समाधान का प्रस्ताव दिया, जिसके बारे में उनके कार्यालय ने कहा कि इसमें स्लोवाकिया सहित कई देशों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। उन्होंने सोमवार को वीडियो संदेश में कहा ?कि स्लोवाकिया की ओर से मैं दोहराता हूं कि हम तैयार हैं। मैं उन रिपोर्टों का स्वागत करता हूं जो पुष्टि करती हैं कि संबंधित वाणिज्यिक कंपनियां पहले से ही इस तकनीकी समाधान को कम से कम समय में लागू करने के तरीके पर विचार कर रही हैं। स्लोवाकिया के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने स्लोवाकिया में हंगरी के राजदूत कसाबा बालोग के साथ एक बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों ने संयुक्त रूप से बाधित तेल आपूर्ति के संबंध में यूरोपीय आयोग से तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

संसद में अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़े

राहुल बोले- अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी

ठाकुर ने कहा- उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद सत्र के सातवें दिन मंगलवार को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा- आपके बोलने के लिए पर्ची आती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले- कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है।

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से बने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा- मैं पूछना हूं कि चाहता हलवा किसे मिला। कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। इनके लिए ओबीसी का मतलब है, ऑनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था, जिसको जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। ठाकुर ने यह भी कहा कि, असत्य के पैर नहीं होते और यह कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवारी करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है। राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। इन टिप्पणियों के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया तो स्पीकर ने राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर के जवाब देने के लिए अनुमति दी।

राहुल बोले- मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- उन्हें पता होना चाहिए कि ओबीसी का फुल फॉर्म लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोपेगैंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी खड़े हुए और कहा- अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, तो हमें जातीय जनगणना चाहिए वह हम करा के रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाए।

बिहार में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के राजनीतिक दल हरकत में आए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।इससे पहले गुरुवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में बताया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से आरक्षण बढ़ाने के फैसले को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की अपील की है।दरअसल इस सूची में शामिल केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।मोदी सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इसके बाद बिहार के राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। उसका कहना है कि नौवीं अनुसूची में पहले से ही 284 कानून हैं। केंद्र सरकार को बिहार के मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने उसकी इस मांग पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। हालांकि उसने जातीय सर्वेक्षण और आरक्षण बढ़ाने का समर्थन किया था। उसको इस बात का डर सता रहा है कि अगर केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को मान लिया तो अन्य राज्यों से इसी तरह की मांग की जाने लगेगी। ऐसे में हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

बिहार जैसे राज्य, जहां की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है, वहां जेडीयू के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला अस्तित्व का सवाल हो सकता है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू पर लगातार इस बात का दबाव डाल रही है कि वह आरक्षण बढ़ाने के फैसले को नौवीं अनुसूची में डालने के लिए बीजेपी पर दवाब बनाए।उसका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के भरोसे है, इसलिए जेडीयू को बीजेपी पर दवाब बनाना चाहिए।राजद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इस मामले की ठीक से पैरवी नहीं की।

वहीं राज्य की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), मुसलमान और सामान्य वर्ग को आनुपातिक आधार पर आरक्षण देगी।

बच्चों पर चाकू से हमला, 3 की मौत

ब्रिटेन(ईएमएस)। ब्रिटेन में लिवरपूल के पास साउथपोर्ट में सोमवार शाम एक नाबालिग ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया। इसमें 3 बच्चे मारे गए हैं। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया गया। घायलों में अधिकतर बच्चे शामिल हैं। यह हमला बच्चों के एक डांस वर्कशॉप में हुआ। पुलिस ने कहा कि 17 वर्षीय हमलावार लडक़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल किए चाकू को जब्त कर लिया है। हमलावर के इरादों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

निकोलस मादुरो की जीत से भड़की जनता, कई देशों ने उठाए सवाल

विपक्ष चुनाव में धांधली का लगा रहा आरोप

वेनेजुएला(ईएमएस)। वेनेजुएला के विभिन्न शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारी एक साथ सड़कों पर उतरे और इस चुनाव का जमकर विरोध किया। सड़कों पर और वेनेजुएला में नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी ऑफिस के बाहर भीड़ देखी गई। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट 28 जुलाई को घोषित किए गए। मादुरो ने तीसरी बार जीत हासिल की। मादुरो ने अपने विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को हराकर 51 फीसदी वोट हासिल किए। हालांकि, विपक्ष की शानदार जीत की पूरी उम्मीद थी। मादुरो और नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी के इस जीत के दावे के बाद से देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

मादुरो की जीत से नाखुश जनता ने सड़कों पर चक्काजाम किया। लोग नारे लगा रहे है यह कहते हुए हम इससे तंग आ चुके हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए आजादी चाहते हैं। माराके शहर में मार्च देखने को मिला जहां लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में बर्तन बजाए। काराकस के एल वैले इलाके में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बता दें कि इस चुनाव का विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग मादुरो से परेशान हो गए है। देश के आर्थिक संकट को लेकर जनता में अंसतोष है। मादुरो लगभग 11 साल से देश की सत्ता पर राज कर रहे है, जिसे हटाने के लिए विपक्षी एकजुट हो गया है। मादुरो 2025 से 2031 तक के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस चुनाव को लेकर दावे किए गए है कि मादुरो ने अधिकांश वैध मतों से जीत हासिल की है। लेकिन, अमेरिका और अन्य जगहों की सरकारों ने इस रिजल्ट पर संदेह जताया है और मतों की पूरी गणना करने की मांग की।

कई देशों ने जताया ऐतराज

कई देशों ने अभी तक वेनिज्वेला के चुनाव नतीजों को मान्यता नहीं दी। साथ ही चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह गंभीर चिंता है कि घोषित परिणाम वेनिज्वेला के लोगों की इच्छा को नहीं दिखाता है। ब्रिटेन ने कहा कि वह गड़बड़ी के आरोपों से चिंतित है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। वोटों की सही गिनती सुनिश्चित करना अहम है।

शिया-सुन्नी के बीच झड़प में 49 की मौत

इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हुए एक जमीन विवाद में 49 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस विवाद की जड़ 30 एकड़ की जमीन है। इसके मालिकाना हक को लेकर कुर्रम जिले के बुशेहरा गांव में दो कबीलों के बीच विवाद है। ये लड़ाई पिछले सप्ताह बुधवार

को दो परिवारों के बीच शुरू हुई थी, जो जल्द ही दो कबीलों के बीच फैल गई। अब इसे लेकर पूरे जिले में तनाव है। सुन्नी समुदाय को सीमा पार के अफगान कबीले का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से वे भारी पड़ रहे हैं। कुर्रम के डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह मेशूद ने लोकल मीडिया से कहा कि दो समुदायों के बीच ये लड़ाई 6 दिनों से जारी है। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर आदिवासी समुदाय जिरगा के बुजुर्गों और दूसरे लोगों की मदद से दोनों समुदायों के बीच समझौता कराया है, लेकिन जिले के दूसरे हिस्सों में अभी भी गोलीबारी की खबरें हैं।

सुन्नी मिदगी और शिया मलीखेल समुदायों के बीच ये विवाद 2007 में शुरू हुआ था। तब भी हिंसा की घटनाएं हुई थीं। पिछले साल जुलाई में भी विवाद हुआ था, जिसके बाद शिया और सुन्नी समुदाय के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें कई लोग मारे गए थे।

क्वाड बैठक से क्या आया संदेश......तिलमिला उठा चीन

टोक्यो (ईएमएस)। चीन पर नकेल कसने के लिए बने भारत और अमेरिका सहित चार प्रमुख देशों के क्वाड (क्वाड) गठबंधन के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में मुलाकात की, जिसमें स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भाग लिया। विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड हिंद और प्रशांत महासागरों में समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप एक स्वतंत्र एवं मुक्त समुद्री व्यवस्था विकसित करने के लिए कटिबद्ध है।

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने चीन को साफ संदेश देकर कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी की दबंगई स्वीकार नहीं की होगी। टोक्यो में इस पर जोर दिया गया कि सभी देश मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर काम करे।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत समूह ने अपने महत्वाकांक्षी हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता (आईपीएमडीए) कार्यक्रम को हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की। यह घोषणा हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं के बीच की गई। एक संयुक्त बयान में विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड हिंद और प्रशांत महासागरों में समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप एक स्वतंत्र एवं मुक्त समुद्री व्यवस्था विकसित करने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेसवार्ता के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड केवल बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि एक ऐसा मंच है, जो सार्थक परिणाम देने की बात करता है। उन्होंने कहा, क्वाड लंबे समय तक टिकने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए है।

क्वाड की बैठक से चीन को लगी मिर्ची

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता से चीन चिढ़ गया है। बैठक के बाद चीन ने अमेरिका और भारत सहित क्वाड समूह के देशों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों के विकास को रोकने के लिए कृत्रिम रूप से तनाव पैदा करने और टकराव भड़काने का आरोप लगाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान पर उनकी प्रतिक्रिया पर कहा कि क्वाड अन्य देशों का विकास रोकने के लिए कृत्रिम रूप से तनाव पैदा कर रहा है और टकराव को भड़का रहा है।

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर लगा बैन, छात्र प्रदर्शन और हिंसा फैलाने का आरोप

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश में एक बड़े घटनाक्रम के चलते सत्ताधारी अवामी लीग के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों के गठबंधन ने कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगाने का फैसला किया है। जमात के साथ ही इसकी शाखा छात्र शिबिर को भी बैन किया जाएगा। जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिबिर पर बीते दिनों बांग्लादेश में हुए छात्र प्रदर्शन को हाईजैक करने और हिंसा फैलाने का आरोप है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

एक रिपोर्ट में बताया था कि आईएसआई से समर्थित जमात-ए-इस्लामी ने आंदोलन को अगवा कर लिया था, जिसके कारण हिंसा और आगजनी हुई। इसके पहले जमात को बांग्लादेश के चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व ने विरोध किया था। उसने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। अक्टूबर 2018 में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जमात-ए-इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था।

सोमवार रात पीएम आवास पर हुई एक बैठक में इसका फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अवामी लीग की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की। बैठक के बाद अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गठबंधन ने आम लोगों की हत्या करने और कई मुद्दे बनाकर आतंकवादी हमले करके राज्य की संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में जमात-शिबिर पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। बीएनपी और जमात देश में अराजकता पैदा करने की साजिश कर रहे हैं।

70 साल बाद जापान में बदल रहा यूएस मिलिट्री कमांड

- पुतिन और किम की दोस्ती से ज्यादा निशाने पर चीन

टोक्यो (ईएमएस)। अमेरिका का कहना है कि वह जापान में अपनी सैन्य कमान का नए सिरे से गठन कर रहा है, क्योंकि दोनों देश चीन से सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि 70 साल पहले सैन्य गठबंधन के बनने के बाद से यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। वाशिंगटन और टोक्यो का कहना है कि वे इलाके में तेजी से बदलते सुरक्षा के माहौल से चिंतित हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने चीन पर पूर्वी और दक्षिण चीन सागर, ताइवान के आसपास और पूरे इलाके में यथास्थिति को बदलने के लिए बलपूर्वक बर्ताव करने का आरोप लगाया है। अमेरिका और जापान के मिलिट्री कमांड का नए सिरे से यह गठन ऐसे समय में हुआ है, जब चीन अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और रूस उत्तर कोरिया के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि यह नया गठबंधन अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संबंधों को कैसे बदलेगा? और चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? बहरहाल यह घोषणा टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तथा उनके जापानी समकक्षों योको कामिकावा और मिनोरू किहारा के बीच सुरक्षा वार्ता के बाद की गई। ऑस्टिन ने मीडिया से कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या के साथ ही जापान में ज्वाइंट फोर्स के मुख्यालय में उन्नत करेगा। यह अमेरिकी सेना की जापान में तैनाती के बाद से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा और 70 साल में जापान के साथ हमारे सैन्य संबंधों में सबसे मजबूत सुधारों में से एक होगा। मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नई कमान संरचना मार्च 2025 तक सेनाओं के लिए एक संयुक्त कमान कायम करने की टोक्यो की अपनी योजनाओं के साथ लागू की जाएगी।

अमेरिका में साम्यवाद फिर उठा रहा सिर, लाल झंडे हाथ में लेकर निकाली रैली

क्लास वॉर 2024 का नारा गूंजा, एलन मस्क ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

फिलाडेल्फिया,(ईएमएस)। साम्यवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक साथ चलने का विचार अकल्पनीय है। इन दोनों का एक साथ चलना और एक साथ अस्तित्व में रहना अपने आप में एक विरोधाभास हो सकता है। साम्यवाद जिसे अब एक पुरातन आंदोलन या विचारधारा माना जाता है उसने एक बार फिर इस पूंजीवादी देश अमेरिका में सिर उठाया है।

दरअसल, रिवोल्यूशनरी (साम्यवाद) कम्युनिस्ट एक वैश्विक आंदोलन है, जो कई देशों में सक्रिय है। अब अमेरिका में भी इसकी शुरुआत हो चकी है। सभा के बाद करीब 500 आरसीए सदस्यों ने हथौड़े और दरांती का चिन्ह वाले लाल झंडे दिखाते हुए फिलाडेल्फिया की सड़कों पर मार्च किया। जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ा क्लास वॉर 2024 का नारा गूंज उठा। आरसीए के मार्च वीडियो पर एलन मस्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

आरसीए ने अपने हैंडल से मार्च का वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, अरबपति परजीवी हैं। एलन मस्क ने आरसीए मार्च के वीडियो कैप्शन पर हैरानी जताई और कॉमेंट सेक्शन में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क पोस्ट किया। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के मालिक एलन मस्क हैं, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में होती है। शायद एक बिलेनियर के स्वामित्व वाले प्लेटफार्म पर अरबपतियों को परजीवी कहने पर एलन मस्क नाराज हुए और उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी है।

एलन मस्क रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ऑफ अमेरिका के पोस्ट पर एक्सक्लेमेटरी मार्क से प्रतिक्रिया देकर यह कहना चाहते थे कि टिप्पणी के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। शायद वह कम्युनिस्ट पार्टी की चुटकी ले रहे थे। एक अन्य पोस्ट में आरसीए ने लिखा-उस पार्टी के साथ जुड़ें जो आपके जीवनकाल में ही पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगी। जब एक यूजर ने आरोप लगाया गया कि रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ऑफ अमेरिका के सदस्य डेमोक्रेट्स के लिए वोट करेंगे, तो आरसीए हैंडल ने जवाब दिया, नहीं. डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों अरबपतियों की पार्टियां हैं। इसीलिए हमने आज एक नई पार्टी की स्थापना की है।

साम्यवाद और अमेरिका, चाहे एक-दूसरे से कितने भी अलग क्यों न हों, इसका मतलब यह नहीं है कि इस पूंजीवादी राष्ट्र पर कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। बता दें 20वीं सदी की शुरुआत में, अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए का उदय हुआ था जिसने श्रमिक आंदोलनों और सिविल राइट्स एक्टिविज्म में अहम भूमिका निभाई थी। वोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ऑफ अमेरिका की स्थापना इसी साल फरवरी में हुई थी। पूरे अमेरिका से कॉमरेड पार्टी के स्थापना समारोह में एकत्रित हुए थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढवासियों को 397करोड़ रुपए के 91विकास कार्यों की भेंट दी

गांधीनगर 30 जुलाई, 2024 : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जूनागढवासियों को 397 करोड़ रुपए के 91 विकास कार्यों की भेंट देते हुए कहा कि राज्य में शहरी विकास में एक भी नगर पीछे न रहे; ऐसी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जूनागढ शहर के इन विभिन्न विकास कार्यों के ई-शिलान्यास व ई-लोकार्पण से ईज ऑफ लिविंग का संकल्प साकार होगा।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी विकास क्षेत्र में राज्य को अग्रिम राज्य बनाने की दिशा दी है। गुजरात अपने शहरी विकास के कारण विश्व पटल पर नामांकित हुआ है। गरवा गिरनार (गौरवशाली गिरनार) की गोद में बसे ऐतिहासिक जूनागढ में भी अत्याधुनिक विकास का राज्य सरकार का लक्ष्य है। नरसिंह मेहता का यह नगर आज विकास की दिशा में अग्रसर बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहरी विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। बढ़ती शहरी जनसंख्या को मूलभूत एवं बुनियादी ढाँचागत सुविधा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में महानगर पालिकाओं तथा नगर पालिकाओं को ढाँचागत विकास के कार्यों के लिए 2111 करोड़ रुपए के चेक प्रदान किए गए हैं, जिसमें जूनागढ महानगर पालिका को 34.40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष बल देते हुए कहा कि जूनागढ मनपा को विकास कार्यों में नंबर वन बनाने का आयोजन हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी साथ मिल कर जूनागढ मनपा को चोटी के स्थान पर पहुँचाएँ। श्री भूपेंद्र पटेल ने केन्द्रीय बजट की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के बजट में शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है। हमारे शहरों को ग्रोथ हब बनने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। गुजरात सहित देश के 100 बड़े शहरों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिल कर वॉटर सप्लाई, सुएज ट्रीटमेंट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट पर भी बजट में बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जूनागढ के लोगों ने यह करके दिखाया है कि लोक भागीदारी से कैसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भारी वर्षा में जूनागढ शहर के नालों में मिट्टी, कीचड़, झाड़ियाँ आदि जमा हो जाने के कारण जल भराव की बड़ी समस्या पैदा हुई थी और इसके कारण काफी नुकसान भी हुआ था, परंतु इस वर्ष जूनागढ महानगर पालिका ने लगभग 9 किलोमीटर लंबे काळवा नाले की पीपीपी मॉडल आधारित डीसिल्टिंग कर इस समस्या का निवारण करने का सराहनीय प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा नाला सफाई कार्यों के लिए जूनागढ नगर पालिका को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री ने ग्रीन ग्रोथ तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल को साकार करने के लिए जूनागढ मनपा द्वारा किए गए 25 हजार पेड़ लगाने के संकल्प का स्वागत करते हुए जूनागढवासियों से इस संकल्प में शामिल होने की अपील की।

कृषि मंत्री तथा जूनागढ जिला प्रभारी मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि जूनागढ शहर क्षेत्र में 397.78 करोड़ रुपए की लागत वाले सीसी रोड, ड्रैनेज लाइन, स्विमिंग पूल, जीआईएस बेस मैचिंग सहित विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा ई-शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से रोजगार सृजन, कर आय में वृद्धि और शहरी व आर्थिक विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारतॅ2047' के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास की अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं।

उन्होंने जोड़ा कि शहर के जोशीपुरा क्षेत्र के व्यापारियों की कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी समस्या भी हल हो गई है। शहर में नरसिंह मेहता सरोवर तथा विलिंग्डन डैम के विकास के कार्य किए जाएंगे और शहर को 25 ई-बसें आवंटित की जाएंगी।

जूनागढ की महापौर श्रीमती गीताबेन परमार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति, हेरिटेज बिल्डिंग नरसिंह मेहता विद्या मंदिर के नवीनीकरण, मनपा क्षेत्र में जीआईएस बेस मैपिंग, सॉलिड वेस्ट सेग्रिगेशन प्लांट, इंद्रेश्वर मंदिर परिसर के विकास सहित विभिन्न विकास कार्यों के हुए शिलान्यास-लोकार्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार के अनुदान से जूनागढ शहर में बहुत विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने जोशीपुरा स्थित कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर की अतिक्रमण समस्याओं के सकारात्मक निवारण के लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया।

मनपा आयुक्त श्री ओम प्रकाश ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, कृषि एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री राघवजी पटेल तथा महानुभावों का स्वागत किया। इस अवसर पर उप महापौर श्री गिरीशभाई कोटेचा, जिला कलेक्टर श्री अनिलकुमार राणावसिया, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री हरेशभाई परसाणा, स्थानीय भाजपा अध्यक्ष श्री पुनीतभाई शर्मा, मनपा में शासक दल के नेता श्री किरीटभाई, सचेतक श्री अरविंदभाई भलाणी, मनपा निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेश पोशिया, आदि महानुभाव एवं जूनागढ के नगरजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

गुजशात में लंबे समय बाद चाशें ही जोन की स्कूल फीस समितियां पुनर्गठित

अहमदाबाद, ३० जुलाई। अहमदाबाद, वडोदश, शजकोट, सूश्त जोन में अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति गुजशात में निजी स्कूलों की फीस तय कश्ने के लिए वर्ष २०१७ में शज्य सश्काश ने गुजशात सेल्फ फायनांस स्कूल (शेग्युलेशन ऑफ फीस) एक्ट पाशित कश्ते हुए फीस समितियां गठित की हैं। शज्य को इस लिहाज से चाश जोन में बांटते हुए फीस नियमन का कार्य इन समितियों को सौंपा है, लेकिन लंबे समय से चाशें ही जोन में से कई सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई थी। इन समितियों के अध्यक्ष से लेकश सदस्यों तक में से ज्यादातश का कार्यकाल पूश हो गया था।

इसे देखते हुए गुजशात सश्काश ने सोमवाश को शज्य की चाशें ही स्कूल फीस समितियों को पुनर्गठित किया है। इनमें अध्यक्ष से लेकश सदस्यों तक की नियुक्तिकी है। इसमें अहमदाबाद, वडोदश, सूश्त औश शजकोट जोन फीस समिति शामिल है। इसमें नियुक्तकिए गए सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का श्हेगा। फीस समिति गठित हो जाने के चलते शज्य के निजी स्कूलों को शहत होगी। उनकी फीस बढ़ाने की मांग पश यह समितियां निर्णय कश्ेंगी।

स्कूलों ने की है फीस बढ़ाने की मांग, अब होगा निर्णयगुजशात शज्य शाला संचालक महामंडल की ओश से शज्य सश्काश से मांग की गई थी कि वह निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि कश्े। दिसंबश में मांग की गई थी कि सश्काश प्राइमशी कक्षाओं की मिनिमम फीस १५ हजाश रुपए से बढ़ाकश २० हजाश रुपए कश्े। माध्यमिक एवं उच्चतश माध्यमिक कक्षाओं की फीस को २५ हजाश से बढ़ाकश ३५ हजाश रुपए किया जाए। क्योंकि सश्काश ने वर्ष २०१७ में फीस नियमन कानून लागू कश्ते समय ही यह मिनिमम फीस निर्धाशित की थी।

अहमदाबाद जोन की फीस नियमन समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हर्षित सी वोश की नियुक्तिकी गई है। स्कूल संचालक मंडल के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में जिगश देसाई, शिक्षाविद सदस्य के रूप में योगेश कुमाश शवल, सिविल इंजीनियश सदस्य के रूप में जिमी पटेल औश सीए सदस्य के रूप में दिव्यांग पढिया को नियुक्तकिया गया है।

वडोदश जोन की फीस नियमन समिति में पूर्व प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मो.हनीफ सिंधी को अध्यक्ष बनाया है। स्कूल संचालक मंडल सदस्य के रूप में धर्मेन्द्र सिंह शजपूत, शिक्षाविद के रूप में जयेश पटेल, सिविल इंजीनियश सदस्य के रूप में डॉ. इंद्रजीत पटेल औश सीए सदस्य के रूप में कृणाल ब्रह्मभट्ट को नियुक्त किया है।

शजकोट जोन की फीस नियमन समिति में सेवा निवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज पी जे अग्रावत को अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्कूल संचालक मंडल सदस्य के रूप में प्रभू सिंधव, शिक्षाविद के रूप में मुकुंदशय महेता, सिविल इंजीनियश प्रविण वसानिया, सीए हार्दिक व्यास सदस्य बनाए गए हैं। सूश्त जोन की स्कूल फीस नियमन समिति में पूर्व प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अतुल शवल को अध्यक्ष बनाया है। स्कूल संचालक प्रतिनिधि के रूप में अमित अग्रवाल, शिक्षाविद के रूप में शांतिलाल पटेल, सिविल इंजीनियश अभिजीत सिंह सोलंकी औश सीए अतुल सोजित्रा को सदस्य नियुक्तकिया गया है।

गांव की ये महिलाएं देती हैं स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा

गांधीनगर 30 जुलाई, 2024 : गुजरात के गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस दिशा में महत्वपूर्ण काम हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप आज गुजरात की ग्रामीण महिलाएं देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का अनोखा उदाहरण बन गई हैं। आज हम बात कर रहे हैं बनास की ड्रोन दीदी आशाबेन चौधरी की, जो गांव में रहकर अपने सपनों को साकार कर रही हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ड्रोन के उपयोग से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2023 से 'नमो ड्रोन दीदी' योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ड्रोन के जरिए खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना सिखाना है। ड्रोन दीदी योजना के तहत 10 से 15 गांवों की स्वयं समूहों की महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें ड्रोन चलाने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण भी शामिल है। गुजरात में ऐसी ही एक ड्रोन दीदी हैं- आशाबेन चौधरी।

बनासकांठा की डीसा तहसील के तालेपुरा गांव की निवासी 31 वर्षीय आशाबेन चौधरी पशुपालन और खेतीबाड़ी से जुड़े परिवार से आती हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है, और अभी ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर आमदनी हासिल कर रही हैं।

ड्रोन उड़ान क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में आशाबेन ने कहा, ''मुझे ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं सखी मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में शामिल होती थी, इसलिए मुझे ड्रोन दीदी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मिली। इस कार्यक्रम के तहत मैंने 2023 में पुणे में 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उससे पूर्व इफको में हमारा इंटरव्यू लिया गया था और फिर मैंने पुणे में परीक्षा दी थी। परीक्षा में हमसे ड्रोन उड्डयन और नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के विषय में प्रश्न पूछे गए। वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने बनासकांठा में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव करना शुरू किया, और आज मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है।''

आशाबेन को मीडियम साइज का ड्रोन, उसे फील्ड में ले जाने के लिए एक ई-व्हीकल और किसी कारणवश कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति से निपटने के लिए एक जनरेटर सेट भी दिया गया है। आशाबेन अरंडी, मूंगफली, पपीता, बाजरी और सौंफ सहित कई अन्य फसलों में ड्रोन की मदद से दवाइयों का छिड़काव कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि केवल छह महीने में उन्होंने इस काम से एक लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की है।

ड्रोन की मदद से कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के फायदों के बारे में आशाबेन ने कहा, ''ड्रोन से छिड़काव व्यवस्थित तरीके से होता है और इससे समय और पैसा; दोनों की बचत होती है। इसमें दवाई और पानी दोनों की मात्रा कम रहती है, लेकिन छिड़काव उचित तरीके से होता है। एक ड्रोन सात मिनट के भीतर एक एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है। सौंफ जैसी ऊंची फसलों में ड्रोन से छिड़काव काफी सुलभ विकल्प है। हम ड्रोन से छिड़काव कराने वाले किसानों का आई खेडूत पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं, ताकि उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति भी मिल सके।''

अब अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर से भी मिलने लगे हैं ऑर्डर

आशाबेन ने बताया कि ड्रोन को संचालित करने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। पहले वे ड्रोन में खेत का नक्शा फीड करती हैं और कम्पास का कैलिब्रेशन कर ड्रोन को निर्धारित क्षेत्र में संचालित करती हैं। इस काम से आसपास के किसानों के बीच उनकी प्रसिद्धि दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ''मुझे तो अब सुरेन्द्रनगर और अहमदाबाद से भी लगातार फोन आ रहे हैं। मुझे इस काम को करने में काफी खुशी मिल रही है। इतना ही नहीं, अब तो आसपास के लोग लड़कियों को मेरा उदाहरण भी देने लगे हैं।''

आशाबेन आशापुरी सखी मंडल संचालित करती हैं, साथ ही वे कई अन्य सखी मंडलों के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे दो बेटियों की मां हैं और उनके परिवार की ओर से भी उन्हें इस काम के लिए पर्याप्त सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है।

उन्होंने राज्य की अन्य महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा, ''सफलता का अर्थ केवल सरकारी नौकरी करना ही नहीं है, सरकार अनेक योजनाएं चला रही है और कई नए क्षेत्रों के द्वार भी खुले हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि वे इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। मैं काम भी करती हूं और अपने परिवार को पर्याप्त समय भी दे पाती हूं।''

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में प्रारंभिक आधार पर लगभग 500 से 1000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने का निर्णय किया गया है, जिनमें से गुजरात राज्य में इफको, जीएसएफसी और जीएनएफसी द्वारा क्रमशः 18, 20 और 20 सहित कुल 58 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान कर ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं।

पश्चिम रेलवे का सुरक्षित एवं सुचारू रेल परिचालन के लिए प्रयासरत

स्वदेशी रूप से विकसित की गई इस तकनीक का उद्देश्य भारतीय रेल की 'ज़ीरो एक्सिडेंट' का लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ऊँझ) प्रणाली है जिसे भारतीय रेल द्वारा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (अएध) के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेनों को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर चलाने में लोको पायलटों की सहायता करता है, तब जब लोको पायलट ऐसा करने में विफल रहता है और खराब मौसम के दौरान ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कवच प्रणाली को आरडीएसओ द्वारा ट्रेनों की गति को 200 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक ट्रेनों को उपयुक्त गति से चलाने में सक्षम बनाएगी। यह सिग्नल पासिंग एट डेंजर (एईंॠ) को रोकने में लोको पायलटों को सहायता करेगी और उन्हें निरंतर गति पर नज़र रखने में सक्षम बनाएगी। सिग्नल के पहलू और गति की हर जानकारी को लोको पायलट के कैब में प्रदर्शित किया जाएगा, जो टकराव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। पश्चिम रेलवे पर, 90 लोको के साथ 789 किमी पर कवच प्रणाली का काम किया जा रहा है। कुल 789 किमी में से 405 किमी के लिए लोको परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और 90 में से 60 लोको को इस तकनीक से लैस किया गया है। पश्चिम रेलवे ने इस वित्त वर्ष 2024-25 में 735 किमी पर इसे कमीशन करने का लक्ष्य रखा है।

आगे की जानकारी देते हुए श्री विनीत ने बताया कि विरार-सूरत-वडोदरा (ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) सेक्शन पर 336 किलोमीटर में से 201 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि वडोदरा-अहमदाबाद (ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) सेक्शन पर 96 किलोमीटर की कवच प्रणाली के लोको ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। वडोदरा-रतलाम-नागदा (नॉन-ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) सेक्शन पर 303 किलोमीटर में से 108 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। अंतिम परीक्षण के साथ-साथ कमीशनिंग का काम भी प्रगति पर है। इसी तरह, मुंबई सेंट्रल-विरार उपनगरीय (ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) सेक्शन के लिए 54 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है।

महिला आत्मनिर्भरता से समृद्धि की ओर गुजरात की विशिष्ट दिशा

गांधीनगर 30 जुलाई, 2024 : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेलगांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में बुधवार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 'सखी संवाद' अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वंय सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) की नारी शक्ति के साथ प्रत्यक्ष संवाद का सेतु साधेंगे।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक उत्थान से उनका जीवन स्तर ऊँचा लाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया जाता है।

राज्य सरकार ने इन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका-उन्मुखी गतिविधियों के साथ जोड़ कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक आयाम शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल बुधवार को समग्र राज्य के 28 हजार से अधिक एसएचजी की सदस्यों यानी नारी शक्ति को कुल 350 करोड़ रुपए के सहायता-लाभ वितरित करने के साथ उनके साथ बातचीत भी करने वाले हैं।

राज्य सरकार ने गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी की स्थापना कर ऐसी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कैश क्रेडिट, ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधा उपलब्ध करा कर सफलता की राह दिखाई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल राज्य की ऐसी सफल ग्रामीण महिला शक्ति के साथ संवाद कर उनकी समस्याएँ जानेंगे और उन समस्याओं को दूर करने का मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।

'सखी संवाद' के इस अभिनव प्रयोग में सहभागी होने वाली 33 जिलों की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल्स भी इस कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाएंगे। बुधवार 31 जुलाई को सुबह महात्मा मंदिर में राज्य के 28 हजार से अधिक स्वयंसहायता समूहों की लगभग तीन लाख माताओं-बहनों को 350 करोड़ रुपए के सहायता-लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ कृषि मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल, राज्य मंत्री श्री कुँवरजीभाई हळपति, गांधीनगर जिले के विधायकगण, गांधीनगर महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव श्री राज कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

आनंदना- कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन और इंडो-डच हॉर्टिकल्चर ने उत्तराखंड में प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल की सफलता का उत्सव मनाया

चंपावत, उत्तराखंड, 30 जुलाई 2024: सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण समारोह में, आनंदना – कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन ने इंडो-डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में उत्तराखंड के चंपावत में प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल के माध्यम से किसानों के अथक प्रयासों को मान्यता दी। इस कार्यक्रम में 10 किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तकनीकों को अपनाने के उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, और स्थानीय कृषि पर इन प्रथाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और श्री राजीव गुप्ता, निदेशक, कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन, श्री सुरेश जोशी, प्रवक्ता भाजपा, श्रीमती ज्योति राय, अध्यक्ष, जिला परिषद चंपावत, श्री प्रकाश तिवारी, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, श्री निर्मल मेहरा, अध्यक्ष, भाजपा चंपावत, श्री नवनीत पांडे, जिला मजिस्ट्रेट, श्रीमती रेखा देवी, ब्लॉक प्रमुख, चंपावत और श्री सुधीर चड्ढा, निदेशक, इंडो-डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज जैसे गणमान्य व्यक्ति समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए।

कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन के निदेशक श्री राजीव गुप्ता ने कहा, ठप्रोजेक्ट उन्नति एप्पल की सफलता स्थायी प्रथाओं के माध्यम से कृषक समुदायों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह परियोजना हमारी बड़ी फ्रूट सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव का हिस्सा है, और इस का उद्देश्य खराब प्रौद्योगिकी और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों के हल निकाल कर किसानों का उत्थान करना है। उन्नत बागवानी समाधान प्रदान करके, हम न केवल किसानों की आजीविका को बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे रहे हैं, बल्कि बेहतर फसल उत्पादन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि भी ला रहे हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का इनिशियल पब्लिकऑफर02अगस्त को खुलेगा

प्राइस बैंड 72/- से 76/- प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है

अहमदाबाद, जुलाई 30

बेंगलुरु स्थित ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर (घ्इ्ध) के लिए ?72/- से ?76/- प्रति इक्विटी का प्राइस बैंड तय किया है। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू ?10/- है। कंपनी का घ्इ्ध सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को खुलेगा और मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 195 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते है। इसके बाद 195 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है। ओला इलेक्ट्रिक भारत में ईवी और ईवी कंपोनेंट के लिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का निर्माण करने वाली एक प्योर ईवी कंपनी है।

घ्इ्ध में 55,000 मिलियन रुपये तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू है। प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स, प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स का 84,941,997 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल (ध्इए) भी शामिल है। प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षण भी शामिल है।

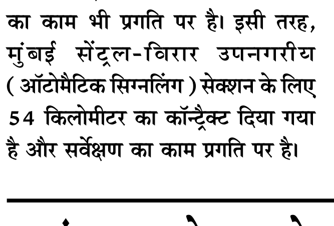

ऑफर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75ÿ क्वालिफाइड इंस्टीटयूशनल बायर्स को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, नेट ऑफर का 15ÿ से अधिक नॉन-इंस्टीटयूशनल बिडर्स को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को आवंटन के लिए नेट ऑफर का 10ÿ से अधिक उपलब्ध नहीं होगा।

सीगल इंडिया लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर 1 अगस्त, 2024 को खुलेगा

अहमदाबाद, 30 जुलाई, 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सीगल इंडिया लिमिटेड ने अपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर (घ्इ्ध) के लिए लिए ?5/- फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड ?380/- से ?401/- तय किया है। कंपनी का घ्इ्ध सब्सक्रिप्शन के लिए गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 को खुलेगा और सोमवार, 5 अगस्त, 2024 को बंद होगा।

निवेशक न्यूनतम 37 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। उसके बाद 37 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में।

घ्इ्ध में 6,842.52 मिलियन रुपये का फ्रेश इश्यू है।

प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स और इंडिविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर्स का 1,41,74,840 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ध्इए) भी शामिल है। फ्रेश इश्यू से मिलने वाले रुपयों में से 997.89 मिलियन रुपये तक का इस्तेमाल उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा; कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, एघ्इ्थ की ओर से लिए गए कुछ उधारों के फुल या पार्ट रीपेमेंट/प्रीपेमेंट के लिए 4,134 मिलियन रुपये; और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए किया जाएगा।

लुधियाना बेस्ड कंपनी के प्रमुख बिजनेस ऑपरेशन्स को मोटे तौर पर ईपीसी प्रोजेक्ट और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (''र्एश'') प्रोजेक्ट में विभाजित किया गया है, जो भारत के दस राज्यों में फैले हुए हैं। 30 जून, 2024 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक ? 94,708.42 मिलियन थी।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर का रजिस्ट्रार है।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95